



उपनिवेशवाद का भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति पर प्रभाव

प्रियंका कुमारी

शोध छात्रा, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, बिहार, भारत।

परिचय

'कोलोनियलिज्म' शब्द लैटिन भाषा के 'कोलोनिआ' से बना है, जिसका अर्थ होता है— एक ऐसी संपत्ति जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों द्वारा कायम किया गया हो। इतिहास में 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा, जिसमें यूरोपियों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपना उपनिवेश बनाया।

शोषण करने एवं प्रभुत्व स्थापित करने का एक ऐसा तरीका, जिसमें किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा अन्य किसी भौगोलिक क्षेत्र में इस उद्देश्य के साथ उपनिवेश (कॉलोनी) स्थापित किया जाता है कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। इसमें किसी शक्ति समूहों द्वारा किसी अन्य क्षेत्र और दूसरे व्यक्ति समूहों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।

उपनिवेशवाद के अन्तर्गत उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रणाली का निर्धारण एवं नियमन उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी देश की अर्थव्यवस्था व पूँजीवादी वर्ग की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के तहत वैश्विक पूँजी बाजार एवं साम्राज्यवादी प्रमुख के अन्तर्गत उपनिवेशों के कई निष्क्रिय या अमौद्रीकृत क्षेत्र भी सक्रिय होकर केन्द्रीय वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाते हैं, परन्तु अधिकांशतः उपनिवेश इस प्रक्रिया में कच्चे मालों का उत्पादनकर्ता बन जाते हैं, जबकि उच्चतर प्रौद्योगिकी एवं उच्चतर उत्पादन क्षमता के बलबूते साम्राज्यवादी देश विनिर्मित मालों का उत्पादन करते थे। विनिर्मित मालों के उत्पादन के लिए कच्चे मालों की पूर्ति के लिए साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी सत्ता लाद देते थे एवं अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से उपनिवेशों में सीमित स्तर पर अवसंरचनात्मक या आर्थिक विकास करने पर भी बल देते थे। इसी प्रक्रिया के तहत विभिन्न देशों एवं विभिन्न अवधियों में उपनिवेशवाद का स्वरूप भी बदलता रहता है। अतः राजनीतिक आधिपत्य की स्थापना उपनिवेशों का मनमाना शोषण करने का प्रभावी माध्यम रहा है।

प्रसिद्ध इतिहासकार 'विपिनचन्द्र' ने उपनिवेशवाद को एक सामाजिक संगठन के रूप में व्याख्यायित किया है, जिसमें सामंतवाद, दास-प्रथा, बन्धुआ मजदूरी, लघु स्तर पर उत्पादन व्यापार, सूदखोरी के कार्य एवं औद्योगिक और वित्तीय पूँजीवादी एक साथ उत्पादन के ये विभिन्न तरीके मौजूद रहते हैं एवं इनके माध्यम से सामाजिक अधिशेष का उपभोग उपनिवेशवादी ताकत के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

1757 ई0 में प्लासी की लड़ाई में सिराज-उद्-दौला की हार को औपनिवेशिक शासन का आरंभ माना जाता है। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की दीवानी ब्रिटिश हाथों में चली गई। (बंगाल राजस्व अंचल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एवं ओडिशा आते थे) ब्रिटिश संसद के घोषणा-पत्र के तहत ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत समेत पूर्व के साथ व्यापार का

एकाधिकार दे दिया गया। इन युद्धों के बाद उन्होंने विजित राज्य क्षेत्रों से भू-राजस्व एकत्रित करने की अनन्य नियंत्रण शक्ति भी अर्जित कर ली। ब्रिटिशों ने अर्थव्यवस्था को अपने सीधे नियंत्रण में लाने के लिए अपनी राजनीतिक नियंत्रण-शक्ति का प्रयोग किया। शीघ्र ही भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों की पूर्ति हेतु बदल दी गई।

साम्राज्यवादी देशों द्वारा अधिगत उपनिवेश मूलतः उनके आर्थिक संदोहन का स्रोत बने। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो भी मौलिक आवश्यकताएँ साम्राज्यवादी देशों ने अनुभूति की, उसे स्थापित किया वह चाहे सत्ता का अधिग्रहण हो या औपनिवेशिक भू-भाग का आर्थिक विकास साथ ही, अपनी लक्ष्यपूर्ति के इस मार्ग में अभीष्ट परिवर्तनों को अपने तरीके से लाने की कोशिश की। साम्राज्यवादी राष्ट्रों का लक्ष्य उपनिवेश का आर्थिक विकास करना नहीं था वरन् उनके आर्थिक ढाँचे में वह सभी परिवर्तन करना था, जिनके द्वारा वे उसका भरपूर संदोहन कर सकें। अतः उन्होंने उपनिवेशों में आर्थिक ढाँचागत परिवर्तन अपने हितपूर्ति हेतु किया। इसी तरह उपनिवेश के नागरिकों को अपने मनोनुकूल उपयोगी बनाने हेतु उनके शिक्षा-स्वरूप एवं सांस्कृतिक ढाँचे में भी तोड़-मरोड़ किया।

भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति को पिछड़ी, अनुपयोगी, बर्बर एवं असभ्य सिद्ध कर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति के निर्माण का प्रयास किया गया, जिससे भारतीयों का एक ऐसा नवीन वर्ग तैयार किया जा सके, जो रंग-रूप से तो भारतीय हो परन्तु मन-मस्तिष्क से अंग्रेजियत की भक्ति करने वाला हो। साथ ही निजी हितों को साधने हेतु भारतीय संस्कृति में निहित अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना पर प्रहार कर तोड़ने का प्रयास किया गया, जो लार्ड मैकाले के वक्तव्यों से स्पष्ट होता है— "मैंने पूरे भारत की लगभग सभी दिशाओं की यात्राएँ की हैं और मुझे इस पूरे दौर में न तो मुझे कोई भिखारी दिखा और न कोई चोर। मैंने इस देश की अमूल्य संपन्नता को देखा है, जहाँ गहरे नैतिक मूल्य व्याप्त हैं और लोग क्षमताओं से लबरेज हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस देश पर विजय पाना हमारे लिए तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम इस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के रूप में मौजूद रीढ़ को तोड़ नहीं देते। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था व भारत की संस्कृति को कुछ इस प्रकार से प्रतिस्थापित करें कि सभी भारतीयों को लगने लगे कि जो कुछ भी उनके देश के बाहर का और अंग्रेजी में है, वह सब अच्छा है और उनकी खुद की चीजों से बेहतर है। इस प्रकार वे अपना स्वविवेक और अपनी देशज संस्कृति को खो बैठेंगे और इस देश पर हमारे प्रभुत्व की जड़ें गहरी करते हुए ठीक वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं।"

इस प्रकार भारतीय संस्कृति एवं समाज की एकता, अखंडता एवं भाईचारे को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया। अंग्रेजी

शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत, पालि एवं फारसी भाषा के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करने के साथ ही पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति भारतीयों में आकर्षण पैदा करना भी था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत की शिक्षा, संस्कृति में किये गये परिवर्तनों का दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिसने एक नये सामाजिक, आर्थिक ढाँचे, नये सामाजिक वर्गों, नई प्रशासन पद्धति तथा एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका भारतीय समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा।

सकारात्मकता इस रूप में दिखाई पड़ी कि औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजी शिक्षा एवं संस्कृति के संसर्ग के फलस्वरूप एक आधुनिक वर्ग उभरा, जिनमें उद्योगपति औद्योगिक श्रमिक एवं शिक्षित वर्ग थे। इस वर्ग ने उस शासन के खिलाफ आन्दोलन खड़ा कर दिया और महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों व धर्मों के पुरुषों व महिलाओं ने एक होकर इस आन्दोलन में भाग लिया। इस आन्दोलन ने लोगों को भारतीयता की अवधारणा से परिचित करवाया और जातिगत व लैंगिक रिश्तों को बदला। जातिगत व लैंगिक रिश्तों में बदलाव लाने में ज्योतिराव फुले, भीमराव अम्बेडकर व पेरियार रामास्वामी नाईकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन व अम्बेडकर जैसे नेताओं ने भारत को "निर्माणाधीन राष्ट्र" बनाया।

अंग्रेजों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर एक समरूप शिक्षा प्रणाली लागू करने का लाभ भारतीयों को मिला। अंग्रेजी आधारित उच्च शिक्षा ने भारत में बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो समरूप चिंतन के कारण उपनिवेशवाद की समरूप आलोचना तक पहुँच सके। 19वीं शदी के उत्तरार्ध में इस शिक्षा का उपनिवेशवाद विरोधी तेवर थोड़ा बहुत भड़कने लगा था।

स्वाभाविक रूप से भारत एक जाति आधारित समाज था। व्यक्तियों की पहचान उसकी जाति एवं धर्म से ही होती थी, उस समय भारतीयों की राष्ट्र सम्बन्धी भावना संकीर्ण थी। छोटी-छोटी रियासतें एवं राज्य स्वयं के छोटे से भूखण्ड को ही राष्ट्र समझते थे, किन्तु नये शिक्षा तंत्र ने नये प्रकार के मूल्यों, मान्यताओं को पैदा करके जाति, धर्म एवं राष्ट्र सम्बन्धी ओछी भावना के बंधन को तोड़कर, उसे एक व्यापक मनो धरातल पर प्रतिष्ठापित किया। अंग्रेजी भाषा विद्या का ज्ञान रखने वाले शिक्षित वर्गों में से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैण्ड चले गये और उन्होंने स्वयं की आँखों से देखा कि एक स्वतंत्र देश में राजनीतिक संस्थाएँ कैसे काम करती हैं? जबकि भारत में स्थिति इंग्लैण्ड की तुलना में भिन्न थी। विदेशों से पढ़कर आये लोगों ने भारत में लगातार बढ़ रहे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध वर्ग के साथ मिलकर भारत में मध्यवर्गीय प्रबुद्ध समाज का निर्माण किया। इस प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय संस्कृति एवं समाज में प्रचलित रूढ़, अस्वस्थ मान्यताओं, परंपराओं एवं कुरीतियों को तोड़कर समाप्त करने का प्रयास किया और अशिक्षित, पिछड़ी सोच के लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आन्दोलनों का सहारा लिया एवं समस्त भारतीयों में ज्ञान की अलख ज्योति जगाने का सफल प्रयास भी किया।

औपनिवेशिक अंग्रेजी शिक्षा के नकारात्मक परिणाम भी निकाले। इस शिक्षा ने शिक्षित और आम लोगों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी, जो स्वतंत्रता के बाद भारत में परेशानी का कारण बनी। साथ ही अंग्रेजी पर बल देने के कारण भारतीय भाषाओं का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया और स्थानीय भाषाएँ बुरी हालत में आ गयी, जिसने जनता में शिक्षा के प्रसार को बाधित किया तथा अंग्रेजी

शिक्षा ने मौलिकता को दबाकर ग्रन्थों को याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। 19वीं शदी के अन्तिम दिनों में ही शिक्षा को अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मान लिया गया था परन्तु भारतीय जनता के ज्यादातर हिस्से के पास शिक्षा तक पहुँच का दरवाजा खुला ही नहीं था। इस प्रकार औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की एक बड़ी कमजोरी जन शिक्षा व्यवस्था का अभाव था। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भी बहुत पिछड़ी हुई थी। अतः दो सौ वर्षों के उपनिवेशवादी शोषण ने भारतीय समाज को पिछड़ेपन का पर्याय बना कर छोड़ दिया।

औपनिवेशिक शासन तंत्र भारतीयों की परस्पर एकता, अखंडता, भाईचारे की भावना को अपने प्रभुत्व की प्रमुख कील, ठोकर मानकर, उसे तोड़ने के उद्देश्य से 'फूट डालो राज करो' की नीति के तहत भारत की सांस्कृतिक-एकता को खंड-खंड करने के लिए भारतीय जनता के एक हिस्से को दूसरे से लड़ाना प्रारम्भ किया। उन्होंने जाति के विरुद्ध जाति, प्रांत के विरुद्ध प्रांत, वर्ग के विरुद्ध वर्ग, एक-दूसरे के विरुद्ध हिन्दू और मुसलमान वर्ग तथा रजवाड़ों और जमींदारों को राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय समाज की हर विभिन्नता का उपयोग भारतीय जनता के बीच आपसी दूरी बढ़ाने के लिए किया। इसमें उन्हें सफलता भी मिलती रही और अंततः वे इस देश को छोड़ने से पहले दो टुकड़ों में बाँट गये।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उपनिवेशवाद ने भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा के मूल में प्रवेश कर आन्तरिक घात द्वारा उसकी मौलिकता, विशिष्टता को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है, जिसमें समस्त संस्कृतियों को आत्मसात् करने की क्षमता है न कि उनके संसर्ग में आकर अपनी विशिष्टता खोने की। इसीलिए तो मुहम्मद इकबाल ने भारतीय संस्कृति को लक्ष्य कर कहा है—

“यूनान-ओ-मिस्र-ओ रुमा, सब मिट गए जहाँ से।
अब तक मगर है बाकी, नाम-ओ-निशाँ हमारा।।
कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।
सदियो रहा है दुश्मन, दौर-ए-जहाँ हमारा।।”

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. आजादी के बाद का भारत – विपिन चन्द्र।
2. आधुनिक भारत का इतिहास – बी० एल० ग्रोवर।
3. आर्थिक विचारों का इतिहास – एम० सी० वैश्व।
4. धर्म और सांप्रदायिकता – नरेन्द्र मोहन।
5. भारतीय संस्कृति की रूपरेखा – गुलाब राय।
6. सभ्यता एवं संस्कृति – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।